

ग्रामीण विकास एवं महिला नेतृत्व

डॉ. जयश्री रणसिंह

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, भासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी, छत्तीसगढ़

ABSTRACT

जिस देश में धरती एवं निदयों को माता की संज्ञा दी जाती है। जहां मां दुर्गा को भाक्ति एवं मां सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया और जहां रानी लक्ष्मीबाई एवं रानी दुर्गावती ने तलवारों से दुश्मनो का सर्वनाश किया उस देश में न जाने अचानक पर्दाप्रथा एवं मिहलाओं का गृह कार्य तक सीमित किये जाने लगा । भारतीय समाज में मिहलाओं का विशिष्ट स्थान रहा लेकिन जहां तक उन्हे पद व अधिकार देने की बात है सिदयों से उनकी उपेक्षा और सही अर्थों में तिरस्कार ही होता रहा है। इसके पीछे आमतौर पर धारणा यह रही है कि मिहलायें कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है जबिक वस्तविकता यह रही है कि मिहलाओं को उनके अधिकारों से विचत रखा गया और सामाजिक और राजनितिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के उनके मार्ग की बाधायें दूर करने के स्थान पर उनमें अड़चने पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब—जब जहां भी मिहलाओं को अवसर मिला, उन्होने न केवल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है बिल्क समाज के उत्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारत में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है। वर्तमान समय की बात की जाए तो महिलाएं पुरुशों से कमतर नहीं हैं। भाहरी क्षेत्रों की महिलाएं पुरुशों से प्रतियोगिता करनें लगी है। और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुशों से कदम से कदम मिला कर चल रही है। छत्तीसढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में परदा प्रथा बिलकुल ही नहीं है। देखा जाए तो भाहरों में अब भी महिलाएं पुरुशों से पीछे चल रहीं है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल पुरुशों की बराबरी करती आयीं हैं बल्कि कई क्षेत्रों में तो आगे भी बढ़ चुकी है। कृशि के क्षेत्र में महिलाओं के बिना कृशि कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कृशि की सारी प्रक्रियाओं में पुरुशों के साथ महिलाएं भी भाग लेतीं है जैसे —रोपा, बियासी, धान कटाई, मिंजाई आदि, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है, दुनिया भर में महिलाओं को स्थानीय सरकार में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ देशों नें ऐसी नीतियां लागू की है जो महिलाओं के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित करती है।

वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इस कारण बहुत से ग्रामों में महिला सरपंच चुनकर आई है। इस संदर्भ में ये धारणा बनी हुई है कि महिलाएं सरपंच अपने कार्य को नहीं कर पाती, उनके कार्य तो उनके पित या पुत्र के द्वारा किया जाता है। सरपंच को बैठको का सभापितत्व करना पड़ता है, सिनितयों में काम करना, सिनितयों के कार्यों का नियंत्रण रखना होता है, ग्राम सभा के कार्यों का संचालन करना पड़ता है और समय—समय पर विकासखण्ड जिला पंचायत के अधिकारियों से तथा भाहरों में जाकर जिला अधिकारियों से मिलना पड़ता है। ये सभी कार्य महिलाएं कैसे कर सकेंगी उनका कार्य केवल हस्ताक्षर करना है और उनके ये कार्य अंततः उनके पितयों को ही करना पड़ेगा।

किंतु ये सब धारणाएं और भांकाए निर्मूल सिद्ध हो रही है। महिलाएं चाहे पंच हो या सरपंच उनकी झिझक दूर होती जा रही है। और वे बराबर आगे आती जा रही है। आज यह देखने में आ रहा है कि जब भी ग्राम पंचायत विकासखण्ड, जिला पंचायत के चुनाव होते है महिलाएं बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी देने लगी है।

KEYWORDS: ग्रामीण क्षेत्र, महिला नेतृत्व, महिला ि क्षा, सामाजिक व्यवस्था।

महिला नेतृत्व :

नारी को सामाजिक अन्याय से छुटकारा दिलाने एवं समानाधिकार प्रप्त करने की चेतना का आगाज हुआ। विभिन्न सामाजिक एवं राजनितिक संगठनो की सिक्यता के फलस्वरुप 1919 में भारतीय नारी के एक छोटे से भाग को एवं सन् 1921 तक पूर्ण मताधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय नारी के ये बढ़ते हुए कदम दुनिया की दृष्टि में आ चर्यजनक थे, क्योंकि यह तो हिन्भू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिकियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी।

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ, क्योंकि नवनिर्मित भारतीय संविधान में महिलाओं को सामाजिक अन्याय से छुटकारा दिलाने व सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्हे पुरुशों के समान अधिकार प्रदान करने हेतु अनेक उपबंध किये गये। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी सन् 1950 में लागू हुआ था। इसने सर्वप्रथम संविधान सभा के उन निर्णयों की घोशणा की जिसमें महिलाओं की सुरक्षा व उनकी स्थिति में सुधार का ध्यान रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नेतृत्व प्रदान करने लगी है। ग्रामीण समाज में बहुत

सामाजिक दोश है — मद्यपान, बालश्रम, बालिववाह, अस्पृ यता, जात—पात, धार्मिक रुढ़ियों, जादूटोना में विश्वास आदि। महिलाओं ने इन सभी सामाजिक दोशों को दूर करनें में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। उन्हे धीरे—धीरे सफलता भी मिल रही है। वैसे कितपय सामाजिक दोश अभी भी बनें हुए हैं। बालश्रम, बालिववाह, के विरुद्ध कानून पास होने के बावजूद ये सामाजिक दोश अभी भी चलते ही जा रहे हैं। इन सब दोशों को दूर करनें के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकास आवश्यक है। शिक्षा के विकास के साथ साथ महिलाएं भी शिक्षित हो लगेंगी और अपने बच्चों को शिक्षित करेंगीं। शिक्षित बच्चे बालश्रम और बाल विवाह जैसे कुप्रथा से दूर होते जाएगें।

तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 :

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने और पंचायती राज संस्थाओं को गतिशीलता व नई दिशा देने तथा उसमें जनता की विशेष कमजोर वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, व महिलाएं सम्मिलित हैं, भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्दे य से 24 अप्रैल 1993 को तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसे 24 अप्रैल 1994 तक लगभग सभी राज्यों के

 $Copyright @ 2023, IERJ.\ This\ open-access \ article\ is\ published\ under\ the\ terms\ of\ the\ Creative\ Commons\ Attribution-NonCommercial\ 4.0\ International\ License\ which\ permits\ Share\ (copy\ and\ redistribute\ the\ material\ in\ any\ medium\ or\ format)\ and\ Adapt\ (remix,\ transform,\ and\ build\ upon\ the\ material)\ under\ the\ Attribution-NonCommercial\ terms.$

विधानमण्डलों द्वारा भी पारित कर दिया गया है। इस 73वें संविधान संशोधन अिधनियम (1993) द्वारा पंचायतों को पूरे देश में समरूपता तथा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अिधनियम द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेदों तथा 11वीं अनुसूची जोड़ते हुए पंचायती राज्य व्यवस्था में प्रावधान किये गयें। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था में प्रावधान किये गयें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। यद्यपि यह अिधनियम अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अिधनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था पंचायत के तीनों स्तरों पर समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था निश्चित रूप से युगान्तकारी है। क्योंकि भारतीय सामाजिक परिवेश में ये वर्ग सर्वाधिक भोशण का शिकार रहे है। हमारे सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से जागरुक व उन्हें सत्ता सम्पन्न बनाने के लिए इस अिधनियम द्वारा पंचायत के तीनों स्तरों पर, सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है।

राज्य में गांव की सरकार में महिलाओं ने धाक जमा ली है। प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है इसके बावजूद वे छत्तीसगढ़ में करीब 60 फीसदी गांवों की सरकार चला रहीं है। यानी अनारिक्षत क्षेत्रों में भी महिलाएं पुरुशों को पीछे छोड़ रही है। प्रदेश में कुल 11 हजार 6 सी 64 ग्राम पंचायतें 146 जनपद पंचायतें तथा 27 जिला पंचायतें है। तीनों इकाईयों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 1 लाख 95 हजार है। इनमें आधे से अधिक पदों पर महिलाएं काबिज हैं। राज्य सरकार ने सन 2008 में महिला आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। तािक इससे पंचायतराज प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ाई जा सके। पंचायत चुनाव से गांव—गांव में महिलाएं नेतृत्व करनें लगीं। जानकारों की माने तो वर्तमान में पंचायत रा संस्थाओं में महिलाओं का दबदबा कायम हो गया है। कहनें को तो आरक्षण मात्र 50 प्रतिशत है, लेकिन निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर नजर डालें तो उनमें से निर्वाचित महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत तक हो गई है।

पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता आई है, क्योंकि महिलाएं गृहलक्ष्मी होने के कारण अन्य सामाजिक दायित्व को भी परिवार की तरह ही निभाती है। जानकीरों के अनुसार यह बदलाव ग्रामीण भारत को नया स्वरूप प्रदान करेगा। पंचायत राज व्यवस्था के संचालन व नियंत्रण का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता है। 73 वें संविधान संशोधन के पूर्व पंचायतों में पुरुशों की प्रधानता होती थी। महिलाओं को अपवाद स्वरूप ही जगह मिल पाती थी, लेकिन 73 वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान किया गया। यह प्रवधान तीनों स्तरों के सभी पदों पर किया गया।

जन अभिव्यक्ति के माध्यम षहरी और ग्रामीण क्षेत्र

भाहरों में मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त कई प्रकार के दबाव समूह और दल होते हैं जो लोगों के बीच प्रचार करते हैं। गांवों में भी मोबाइल, टेलीविजन का प्रवेश हो चुका है। पंचायत भवन में कई प्रकार के समाचार प्रत्र आते हैं, विशेषकर दैनिक अखबार जो पास के नगरों से निकलते हैं। ये सभी हिंदी में होते है। ग्रामीण विशेषकर पंच, सरपंच इनको सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं, इससे ग्रामीणों का राजनैतिक सामाजिकरण होता रहता है। ग्रामीणों के संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ता है। भाहरी क्षेत्रों के सदृश्य ग्रामीणों का राजनैतिक संस्कारण बदल रहा है। गेब्रियल ए आमंड ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर नागरिक संस्कृति में व्यक्ति के राजनैतिक संस्कारों के तीन पहलू बतलाये हैं – ज्ञानात्मक, भावात्मक, और मूल्यांकनात्मक।

जहां तक ज्ञानात्मक संस्कारण का प्रश्न है मैंने धमतरी जिले के बहुत से ग्रामों का भ्रमण किया, इन सभी में मुझे लगा कि ग्रामीणों का संस्कारण दिन ब दिन ऊँचा होता जा रहा है। समाचार पत्रों पत्रिकाओं में जो खबरें प्रकाशक होते हैं उनको पढ़ने वाले लोग ग्राम के अन्य व्यक्तियों को बतलाते हैं। महिलाएं घर पर हो या खेतखार में काम कर रही हो महिला मंडिलयों में बैठी इन समाचारों को दूसरों को बतलाती रहती हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ और राष्ट्र की प्रमुख बातें पूरे गॉव में प्रचारित हो जाती है। साथ ही टी.वी., रेडियो, मोबाईल, के समाचारों को भी लोग सुनने लगे हैं। यद्यपि सभी उतनी रूचि से इन्हें नहीं सुनते फिर भी रूचि लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल में पढ़नें वाले विद्यार्थियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। स्कूल से निकलने के बाद ये भी क्षेत्र और राष्ट्र के समाचारों में रूचि लेने लगते हैं।

इस प्रकार ग्रामीणों के ज्ञानात्मक संस्कारण का स्तर बढ़ता जा रहा है और पुराने अंधविश्वास, रूढ़ियाँ बड़ी तेजी से समाप्त हो रही है। उदाहरण के लिये जाति प्रथा पर महिला सरपंचों और अन्य ग्रामीण महिलाओं से जितने भी प्रश्न इस संबंध में पूछे गये सभी ने कहा कि अब हमारे गाँव में सब समान है, जाति का कोई भेद नहीं है। हम सबके हाथ का पानी पी लेंगे, एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर भी किसी महिला या महिला सरपंच ने यह नहीं कहा कि मैं जात—पात मानती हूं या छुआछूत मानती हूं। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि छत्तसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से छुआछूत, ऊँच नीच, अस्पृ यता की भावना मिट चुकी है या मिटती जा रही है? इस पर मैं अपन स्पश्ट मत नहीं व्यक्त कर सकती, क्योंकि खेत खार, खिलहान, मंदिरों, पूजास्थलों में लोगों में व्यवहार का गहराई से अध्ययन अवलोकन आवश्यक है। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में खैरलांजी तथा हाथरस सदृभय कोई घटना नहीं घटित है। इस दृष्टिर से छत्तीसगढ़ को भारत के महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि कई राज्यों से अधिक सभ्य अधिक विकसित राज्य कहा जा सकता है।

राजनैतिक संस्कारण के दूसरा पहलू हैं भावात्मक पहलू। व्यवस्था में चल रही विविध बातों के प्रति इनका कितना लगाव है। अर्थात् वे विविध योजनाओं से कितना लगाव या निकटता महसूस करते हैं। जैसे कि रोजगार गारंटी योजनाएं उनके लिये कितनी कारगर हो रही है। राजनैतिक संस्कारण का तीसरा अभिमुखिकरण है मूल्यांकनात्मक अभिमुखिकरण। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विविध समस्याओं का किस प्रकार से मूल्यांकन करती है। भाहरी महिलाएं विविध क्षेत्रों में उतना खुलकर भागीदारी नहीं कर पाती हैं या उनको उतना अवसर नहीं मिल पाता है। ग्रामीण महिलाएं घर में, खेत में निर्माण के स्थलों पर और ग्राम के राजनैतिक जीवन में पुरुशों के साथ मिलकर भागीदारी करती है।

महिला सरपंच ग्रामीण सम्भ्रान्तजनों के रूप में

क्या महिला सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में उनको प्रदत्त राजनैतिक भाक्तियों का उपयोग करके ग्रामीण जीवन को समुचित नेतृत्व प्रदान कर रही हैं ? इस विशय पर मुझे एक अखबार में प्रकाशक यह टिप्पणी पढ़ने का अवसर मिला इस अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि महिलाए पंचायती राज व्यवस्था में बड़ी सशक्त भूमिका निभा रही है। इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से वे देश की राजनैतिक व्यवस्था में बड़ी प्रभावी भूमिका अदा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा और सांस्कृतिक संगठन ने पश्चिम

गांव में आया बदलाव

महिला आरक्षण से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। बच्चों के शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति पुरुशों के मुकाबले ज्यादा गंभीरता दिखाई है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत एवं मृत्युभोज जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में मद्दगार साबित हुई है। नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का बीड़ा भी महिला जनप्रतिनिधियों एवं स्व सहायता समूह ने उठाया गया है महिलाओं का नशाखोरी के खिलाफ चलाया जा रहा आंदोलन किसी सामाजिक क्रांति से कम नही। गांव में भुद्ध पेयजल व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं महिला सुरक्षा पर जागरुकता का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उनकी जागरुकता से नशामृक्त समाज की स्थापना में मदद मिलेगी।

महिला सरपंच ग्रामीण सम्भ्रान्तजनों के रूप में षिक्त के स्वरूप की विवेचना

क्या महिला सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में उनको प्रदत्त राजनैतिक भाक्तियों का उपयोग करके ग्रामीण जीवन को समुचित नेतृत्व प्रदान कर रही है? इस विशय पर मुझे एक अखबार में प्रकाशक यह टिप्पणी पढ़ने का अवसर मिला, इस अध्ययन में इस बात पर बल दिया गया है कि महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में बड़ी सशक्त भूमिका निभा रही है। इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से वे देश की राजनैतिक व्यवस्था में बड़ी प्रभावी भूमिका अदा करेंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा और सांस्कृतिक संगठन ने पश्चिम बंगाल को 66 ग्रामों का इस रिपोर्ट में अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान के 100 ग्रामों का भी एक प्रतीक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उन ग्रामों में जहां महिला प्रधान हैं वहां परिवार नियोजन के कार्यक्रम सफल हुए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे ग्रामों ने विकास किया है। ऐसे ग्रामों में लड़िकयों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है।

संसद में यह रिपोर्ट उस समय प्रकाशक हुई है जब महिला आरक्षण का विधेयक नेताओं के संकुचित दृष्टी वाले राजनीतिज्ञों के कारण अटका पड़ा था। इस रिपोर्ट का "the state of the world children 2007" में पश्चिम बंगाल के 165 ग्रामों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भागीदारी करने का आरक्षण के माध्यम से जो अवसर प्रदान किया गया है उसके कारण सभी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को बढावा मिला है। इन गांव में पेयजल पर पुरुश सरपंच वाले गांव की तुलना में महिला सरपंच वाले गांव में पेयजल का दुगुना प्रबंध किया गया है। ऐसे गांव में स्वास्थ्य अधिकारियों का बारबार आगमन हुआ है। महिलाओं के कारण इन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों में लड़िकयों की संख्या बढ़ी है। पेयजल की आपूर्ति, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हुआ है।

यूनीसेफ के एक अध्ययन में कहा गया है कि महिलाएं, पुरुशों की तुलना में समाज में अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

निश्कर्श छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के पंचायत एक्ट को लगभग उसी रूप में बिना विशेष संशोधन के अपनाया गया, केवल इधर उधर कुछ ही संशोधन किये गये। इन थोड़े से संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ पंचायती एक्ट 2001 पारित किया गया और इसके अंतर्गत पंचायत चुनाव हुए। जो संशोधन किये गये थे वे प्रमुख रूप से दो थे।

- पंच सरपंच पदों के लिये उम्मीदवार को कम से कम प्राथिमक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
- 2) उसके दो से अधिक संताने नहीं होना चाहिए।

इन संशोधनों का उद्देश्य बहुत अच्छा था। पढ़ा लिखा पंच सरपंच अपने ग्राम समाज और राज्य और राष्ट्र के बारे में अपढ़ पंचो सरपंचों से अधिक अच्छी जानकारी रख सकता है। उसमें परिवेश को समझने की क्षमता अधिक होती है। और दूसरा छोटा परिवार जिससे संतानों का लालन पालन ठीक से हो पाये। किंतु इस अधिनियम को अदालत में चुनौंति दी गयी। 2004 के पंचायती अधिनियम में इन दोनों निर्योग्यताओं को हटा दिया गया।

आज ग्रामीण बहुत जाग्रत हो गये है। पंचायत चुनाव उनमें बहुत अधिक जागृति उत्पन्न कर रहे है। राज्य या राष्ट्रीय चुनाव प्रत्याशिओं के बिना गांव में प्रवेश किये जीतना संभव नहीं है। ग्रामीण मतदाता लगातार अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करता रहता है। वर्तमान में राजनैतिक भाक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। इन संस्थाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण इस प्रकार से 3 जातियों वर्गों से भरा जाना है। इस प्रकार ग्रामों में महिला नेतृत्व भी उभरने लगा है। महिलाएं, प्रारंभ में कुछ हिचकिचाती थीं किन्तु धीरे—धीरे वे राजनीतिक जीवन में कार्य करने की अभ्यस्त होती जा रही है। अब महिलाएं भी राजनैतिक भाक्ति के महत्व को पहचानने लगी है। अब इन महिला पंच सरपंच के पद पर काफी प्रतिद्वंदिता होने लगी है। सरपंच के पद पर तो एक की ग्राम से कई महिला प्रत्याशि खड़ी हो जाती है और चुनाव संधर्श पूर्ण हो जाता है।

संदर्भग्रंथ

- 1. सी राइट मिल्स— दि पावर एलीट्स, न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1954 पृ. 1
- 2. काशी प्रसाद जायसवाल हिन्दू पोलिटिक्स, कलकत्ता, 1920, पृ. 75–80
- 3. थॉमस हिल ग्रीन प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल आबलिगेशन, एबेनस्टीन में (पू.उ.)।
- 4. बेर्डन पावेल दि इंडियन विपेज, आक्सफोर्ड, 1905 पृ. 1
- 5. पंचायत एक्ट धारा 19,6,7
- 6. अनुच्छेद 243, A,B,C,D,E,F,